

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 01

अंक - 332

बेमेतरा, शनिवार 19 जुलाई 2025

रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित

कुल पेज - 8

मूल्य - 5 रुपये

संक्षिप्त समाचार

वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप : घाट जलमग्न, प्रशासन ने लोगों को किया सचेत

वाराणसी। उत्तर भारत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। धार्मिक नगरी काशी में मां गंगा उफान पर हैं, जिसके चलते वाराणसी के प्रसिद्ध 84 घाटों में पानी भर गया है। कई घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं, और घाटों के किनारे बने मंदिरों में भी पानी घुस गया है। खास तौर पर अस्सी घाट, जो पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है, पूरी तरह डूब चुका है। यहां हर सुबह होने वाला सुबह बनारस का मंच भी गंगा की लहरों में समा गया है। स्थानीय प्रशासन ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों को गहरे पानी में न जाने की चेतावनी दी है। घाटों पर लगातार मुनादी की जा रही है और छोटी-बड़ी सभी नौकाओं के संचालन पर रोक लगा दी गई है।

आरोपी को नहीं पता था उसने फौजा सिंह को टक्कर मारी

जालंधर। 114 वर्षीय प्रसिद्ध धावक फौजा सिंह से जुड़े हिट एंड रन मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जालंधर पुलिस ने अहम खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी को फौजा सिंह के बारे में कुछ नहीं पता था। आरोपी हादसे के कारण डर गया और घटनास्थल से गाड़ी लेकर भागा।

भिलाई/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम ने आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास में छापा मारा। ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर विशेष कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झुमाझुट की हुई। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार भिन्न गरमा गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं पार्टी ने ऐलान किया

है कि 19 जुलाई को पूरे प्रदेशभर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला दहन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेजा गया है। जिसमें सभी जिला मुख्यालयों में पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सांसद, विधायक, पार्षद, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर जिस तरह से छापा मारा, वह पूरी तरह से बदले की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बघेल के परिवार को डराने और धमकाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अब इस सरकार से बुरी तरह त्रस्त हो



चुकी है। यही वजह है कि कभी केंद्रीय मंत्रियों के काफिले को रोका जा रहा है, तो कभी उपमुख्यमंत्री की गाड़ियों को। सत्ता पक्ष के सांसदों तक को अब जनता का सामना करने में मुश्किल हो रही है। ईडी के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला दहन यह छत्तीसगढ़ की जनता को भी मंजूर

नहीं है। दीपक बैज ने साफ किया कि यह कार्रवाई लोकतंत्र के खिलाफ है और कांग्रेस इसका जोरदार विरोध करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि 19 जुलाई, शनिवार को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सरकार डराने की कोशिश कर रही है। ईडी के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला दहन किया जाएगा। कांग्रेस ने ईडी की

कार्रवाई को सत्ता का दुरुपयोग बताया है और आगामी 19 जुलाई को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुट गई है। आज सुबह 6 बजे ईडी की टीम ने भिलाई स्थित भूपेश बघेल के आवास पर छापा मारा। यह छापा शराब घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है। करीब 8 अधिकारियों की टीम दो गाड़ियों में पहुंची और इस दौरान छानबीन के बाद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार कर रायपुर की न्यायधीश डमरूधर चौहान विशेष कोर्ट में पेश किया गया। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है, जहां उनसे शराब घोटाले में पछताछ की जाएगी। अब चैतन्य बघेल को श्वश्रु की टीम 22 जुलाई को शाम 4 बजे विशेष कोर्ट में पेश करेगी।

पूर्व सीएम बघेल बोले-तोहफे के लिए धन्यवाद, ताउम्र याद रहेगा

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। इसके बाद ईडी ने चैतन्य बघेल को रायपुर कोर्ट में पेश किया है। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, भूपेश बघेल रायपुर जिला कोर्ट पहुंच रहे हैं। बता दें आज छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था। सत्र के बीच में ही ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट किया। आज सुबह ही पूर्व सीएम के भिलाई आवास पर ईडी का छापा पड़ा था।



भुवनेश्वर के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में आग

लगभग 60 से अधिक लोगों को बचाया गया

भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में शुक्रवार को आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि घटना के दौरान कॉलेज परिसर में मौजूद छात्रों सहित 60 से अधिक लोगों को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। यह घटना शहर के जगमारा क्षेत्र में स्थित कॉलेज में प्रशिक्षण सत्र के दौरान घटी। अग्निशमन दलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुमंजिला इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकाला। अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रमेश चंद्र माझी ने कहा,



हमने लगभग 60 लोगों को बचाया और उन्हें पास के अस्पताल में भेजा है। उन्होंने कहा, आग लगने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि प्रभावित लोगों को 10 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया।



अनंतनाग ज़िले में अमरनाथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं।

जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी के बाद गुरुवार को जम्मू से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई।

रूसी महिला और बेटे का अब तक कोई सुराग नहीं

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया जारी हुआ लुकआउट नोटिस...

नई दिल्ली। दिल्ली में एक रूसी महिला द्वारा अपने चार साल के बेटे को लेकर लापता होने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि महिला ने देश को किसी वैध रास्ते से नहीं छोड़ा है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। यह मामला एक भारतीय पिता और रूसी मां के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा है। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय ने पूरे देश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को महिला को ढूँढने के लिए लुकआउट नोटिस और ह्यू एंड क्राय नोटिस जारी किए



हैं। महिला और बच्चा अभी भी लापता हैं और उन्हें ढूँढने के प्रयास जारी हैं। न्यायमूर्ति सुर्यकांत और उनकी पीठ ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे दिल्ली-एनसीआर के सभी रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाओं से संपर्क कर महिला की संभावित आवाजाही की जांच करें।

विजय शर्मा जन्मदिन विशेष...

19 JULY

छत्तीसगढ़ सरकार के **"हिंदुत्व फायरब्रांड"** और लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री **श्री विजय शर्मा जी** को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं...

एक सामान्य कार्यकर्ता से छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री तक का सफर - यह विजय शर्मा जी की कड़ी मेहनत, स्पष्ट विचारधारा और जनसेवा के प्रति समर्पण का परिचायक है

राजनीतिक जीवन की शुरुआत व सफर

- राजनीति में कदम एक स्वयंसेवक के रूप में रखा
- 1989 से ABVP के सक्रिय कार्यकर्ता
- 2016-2020: भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य अध्यक्ष
- 2020: कबीरधाम जिला पंचायत सदस्य बने
- बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कार्य किया
- भाजपा के प्रदेश महासचिव/महामंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई
- 2023 में पहली बार विधायक बने, कचवर्ती सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अकबर को भारी मतो से हराया
- 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली

गृह मंत्री के रूप में मजबूत नेतृत्व

- श्री विजय शर्मा जी को गृह मंत्रालय जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है
- राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में उनकी विशेष भूमिका रही है
- विशेषकर बस्तर में नक्सलवाद पर प्रहार कर शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है
- उन्होंने स्पष्ट कहा: **"सरकार नक्सलियों से शत्रुवैरुत बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते वे भारतीय संविधान को स्वीकारें, गवर्नरसरा स्वीकार्य नहीं होगी।"**

विकास और संकल्प का चेहरा

- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्री विजय शर्मा जी ने ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान, और रोजगार जैसे विभागों में तेज़ रफ्तार से कार्यों को आगे बढ़ाया
- आज वे छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक स्वच्छ, विचारशील और प्रभावी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं

"हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता", "जनता के बीच से उठे जननायक" और "छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़े कर्मयोगी"

यह सभी उपाधियाँ उन्हें जनता ने स्वयं दी हैं।

उनकी कार्यशैली, भाषण, जनसंपर्क और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित नेतृत्व आज की युवा पीढ़ी के लिए आदर्श हैं।

योगेश तिवारी

राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व हिन्दू सनातन संगठन
भाजपा किसान नेता, बेमेतरा

श्रीमती कल्पना योगेश तिवारी जी

जिला पंचायत अध्यक्ष, बेमेतरा

मरकाम,जिलाध्यक्ष बुधराम नेताम,पूर्व जिलाध्यक्ष झुमक दीवान,जिला कांग्रेस कमेटी प्रभारी महामंत्री खिशन पटेल,महामंत्री गीतेश गाँधी,संजु देवान,कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष सक्कराकरन,कार्यकारी शहर अध्यक्ष नरेंद्र देवांगन,कोषाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी हरमोहन कोहली,शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति हेमल देवांगन,भववती पटेल,गुणमती नायक,उमदी देवान,लेखनी प्रधान,अंजू जोशी,नीलू देवांगन,प्रीति भदौरिया, सरिता देवांगन,भंवर कौशल पटेल, शिवलाल मंडावी,सन्न आनंद,भरत देवांगन,मंडल अध्यक्ष नंदू दीवान, योगेंद्र राठौड़, ब्रज सोढी,योगेंद्र पोयाम, राजेंद्र देवांगन,गुलशकु, रमेश सिन्हा,संतोष नाग,श्यामलाम बघेल,शेख आदिल, रायसिंग मंडावी,दीन देताम,देवेंद्र कोराम, जीतू दुबे,हीरा दीवान,रविन दीवान,लोकमन दीवान,लक्ष्मण पांडे, सतीश देताम,धुष्पी ध्रुव,बलदेव मरकाम, वरुण नेतुषि,जययाम मरकाम,पीलाराम नेताम सहित 500 की संख्या बल के साथ कांग्रेस पदाधिकार कार्यकर्ता किसान एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

संपादकीय

गुजरात के अहमदाबाद में बीते जून माह में हुए विमान हादसे की प्रारंभिक जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रपट में कहा गया है कि दुर्घटना से ठीक पहले विमान के दोनों इंजन में ईंधन पहुंचाने वाले स्विच बंद हो गए थे, जिससे पायलटों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। भ्रम इस बात का कि स्विच किसमें बंद किए। यह तकनीकी खराबी के कारण हुआ या किसी की गलती से, रपट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यानी हादसे के एक कारण का तो पता चल गया, लेकिन इस कारण के पीछे असल वजह क्या थी, यह सवाल अब भी अनुत्तरित है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों को आपस में मर्ज (विलय) करने का फैसला किया तो इस पर राजनीति और हंगामा शुरू हो गया । विपक्षी नेता इस नीति को छात्रों के विरोध में बताते हुए बयानबाजी करने लगे, शिक्षकों की ओर से भी इस नीति का विरोध जताया जाने लगा, अभिभावक भी चिंतित होने लगे, कोई इस नीति के विरोध में कोर्ट चला गया तो कोई सोशल मीडिया पर इसके विरोध में तमाम पोस्टें किये जा रहा है ।

उप्र में विद्यालय विलय नीति का विरोध करने वाले बच्चों के भविष्य पर राजनीति कर रहे हैं

(नीरज कुमार दुबे)

असल में देखा जाये तो योगी सरकार की स्कूलों को मर्ज करने की नीति केवल प्रशासनिक सुधार भर नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधनों की बेहतर उपलब्धता और विद्यार्थियों के समग्र विकास के दृष्टिकोण से एक दूरदर्शी कदम है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों को आपस में मर्ज (विलय) करने का फैसला किया तो इस पर राजनीति और हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी नेता इस नीति को छात्रों के विरोध में बताते हुए बयानबाजी करने लगे, शिक्षकों की ओर से भी इस नीति का विरोध जताया जाने लगा, अभिभावक भी चिंतित होने लगे, कोई इस नीति के विरोध में कोर्ट चला गया तो कोई सोशल मीडिया पर इसके विरोध में तमाम पोस्टें किये जा रहा है। लेकिन आप इस नीति का विरोध कर रहे लोगों की बातों को सुनेंगे या उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ेंगे तो एक बात साफ हो जायेगी कि इन्हें शिक्षा में सुधार से कोई लेना-देना नहीं है। किसी को अपना राजनीति चमकानी है तो किसी को अपने लिये बरसों से बने सुविधाजनक माहौल से बाहर नहीं निकलना है।

जबकि असल में देखा जाये तो योगी सरकार की स्कूलों को मर्ज करने की नीति केवल प्रशासनिक सुधार भर नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधनों की बेहतर उपलब्धता और विद्यार्थियों के समग्र विकास के दृष्टिकोण से एक दूरदर्शी कदम है। इस नीति के दूरगामी प्रभाव छात्रों और उनके अभिभावकों के हित में साबित होंगे। हम आपको बता दें कि 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों को पास के ज्यादा छात्रों वाले विद्यालयों में समायोजित कर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना ही इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस नीति को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज किया जाना इस नीति की वैधता का प्रमाण भी है।

स्कूलों को मर्ज करने की नीति का विरोध करने वालों को समझना चाहिए कि छोटे-छोटे विद्यालयों में अवसर मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिलती है। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, स्मार्ट क्लास, साफ पानी और शौचालय जैसी बुनियादी चीजों का भी अभाव होता है। जब दो या तीन स्कूलों को मर्ज कर एक बड़ा स्कूल बनाया जाएगा, तो संसाधनों का केन्द्रीयकरण होगा। इससे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल, अच्छे बिल्डिंग, खेल-कूद और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इसके अलावा, अभी कई स्कूलों में एक या दो अध्यापक ही पूरे विद्यालय का भार उठा रहे हैं। इससे न तो शिक्षक विषय विशेषज्ञ बन पाते हैं और न ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। मर्ज किए गए बड़े स्कूलों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराना सरकार के लिए आसान होगा। इससे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों में भी बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सकेगा।

साथ ही मर्जिंग के बाद स्कूलों में केवल छात्र संख्या ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि प्रतियोगिता, नवाचार और गतिविधियों के अवसर भी बढ़ेंगे। बड़े स्कूलों में सामान्यतः बेहतर शैक्षणिक माहौल होता है, जिससे बच्चों के सीखने का स्तर स्वतः ही ऊपर उठता है। इससे बच्चों की नींव मजबूत होगी और आगे चलकर

विमान हादसे के पीछे असल वजह क्या थी? कई अनसुलझे सवाल

एअर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में सवार 242 लोगों में से एक को छोड़कर बाकी सभी की इस हादसे में मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं, जिनका जवाब इसलिए भी तलाशना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी बड़ी त्रासदी को रोकने के पुख्ता बंदोबस्त किए जा सकें। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआइबी) की रपट के अनुसार, एअर इंडिया के इस विमान के उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद इसके दोनों ईंधन नियंत्रण स्विच (जिनका उपयोग इंजनों को बंद करने के लिए किया जाता है) अचानक बंद हो गए थे। इसकी

पुष्टि घटना के वक्त ‘काकपिट वायस रेकाडिंग’ में पायलट और सह-पायलट की आपसी बातचीत से हुई है। जांच रपट में कहा गया है कि बातचीत के दौरान एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि ईंधन की आपूर्ति क्यों बंद की गई, तो जवाब मिला कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे साफ है कि हादसे से पहले विमान के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों ईंधन नियंत्रण स्विच एक साथ बंद कैसे हो गए। नियमानुसार उड़ान से पहले विमान की तकनीकी जांच की जाती है और सभी मानकों पर संतोषजनक रपट के बाद ही उड़ान की

अनुमति दी जाती है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि अगर एअर इंडिया के इस विमान में कोई तकनीकी खराबी थी, तो वह उड़ान से पहले की जांच के दौरान पकड़ में क्यों नहीं आई? हादसे की आगे की जांच में इन आशंकाओं से जुड़े सवालों को भी शामिल करने की जरूरत है। जांच रपट का दूसरा पहलू यह है कि कहीं अनजाने में पायलट की गलती से ईंधन नियंत्रण स्विच बंद तो नहीं हुए थे ! हलाकि, रपट में विमान के पायलटों की गलती की ओर स्पष्ट रूप से कोई संकेत नहीं किया गया है। वहीं, विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि पायलटों

द्वारा ईंधन स्विच को अनजाने में चालू या बंद करने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि स्विच में एक छोटा ‘मैकेनिकल गेट’ लगा होता है। रपट में कहा गया है कि दोनों पायलटों ने इंजनों को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन एक इंजन ही ठीक हो पाया, जबकि दूसरा गति बढ़ाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाया। यानी पायलटों ने उस नाजुक घड़ी में हार नहीं मानी थी और उन्होंने वह हर कोशिश की जो संभव थी। इसके अलावा विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने इस हादसे के पीछे किसी साजिश की आशंका को भी अभी तक दरकिनार नहीं किया है।

मुस्लिम आबादी में इजाफा, हिंदुओं की घट रही हैआबादी

(दिनेश मिश्र)

दुनिया में इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। बीते वर्षों में इसे मानने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसी क्रम में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया की आबादी पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिसर्च के अनुसार, अगले कुछ दशकों में यह आबादी और भी तेजी से बढ़ेगी। इससे पहले प्यू रिसर्च की ही एक स्टडी के अनुसार, 2060 तक दुनिया में मुसलमानों की आबादी 70 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि 2060 तक दुनिया में 300 करोड़ से ज्यादा मुसलमान होंगे। यह भी अनुमान है कि उस वक्त तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा, जो ईसाई धर्म को पीछे छोड़ देगा। अभी दुनिया में ईसाई धर्म मानने वालों की आबादी सबसे ज्यादा है। ट्र्यूजुड ट्रेविया में इसे विस्तार से समझते हैं।

एक दशक में ईसाइयों से ज्यादा बढ़ गए मुस्लिम: प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक, 2010 से 2020 के बीच मुस्लिमों की आबादी 34.7 करोड़ बढ़ गई। अब पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी 200 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। वहीं, इस दौरान ईसाइयों की आबादी में 12.2 करोड़ का इजाफा हुआ, जो इस वक्त 230 करोड़ के पार हो चुकी है। वहीं, बौद्धों की आबादी 1.9 करोड़ कम हो गई, जो अब 32.4 करोड़ रह गई है। मुस्लिमों के मुकाबले गैर मुस्लिमों की आबादी इस दौरान 24.8 करोड़ ही बढ़ी, जो मुस्लिमों के इजाफे से काफी कम है।

क्या 35 साल में दुनिया में होगा इस्लाम का राजः प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, अभी दुनिया में ईसाई धर्म सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म है। दुनिया की 730 करोड़ आबादी में से 31 प्रतिशत ईसाई है। इस्लाम दूसरे नंबर पर है और हिंदू धर्म तीसरे नंबर पर है। लेकिन प्यू रिसर्च की स्टडी के अनुसार, अगले 35 सालों में यह स्थिति बदल जाएगी। मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। स्टडी में बताया गया है कि इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। यह लगातार बढ़ रहा है और 2060 तक मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी। यहां राज शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक या सामाजिक प्रभुत्व के अर्थ में किया गया है।

मुसलमानों की आबादी बढ़ने के पीछे ये हैं बड़े कारण: मुसलमानों की आबादी तेज से बढ़ने के पीछे तीन मुख्य कारण हैं-युवा आबादी, ज्यादा बच्चे पैदा होना और धर्म परिवर्तन। दुनिया की आबादी 2060 तक लगभग 32 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान

है। लेकिन मुसलमानों की आबादी 70प्रतिशत तक बढ़ सकती है, जो कि दुनिया के औसत से दोगुना है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में मुसलमानों की आबादी बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण उसका युवा होना।

दुनिया में मुस्लिम आबादी ज्यादा युवा : प्यू रिसर्च की स्टडी में 2015 से 2060 के बीच के 45 सालों का अनुमान लगाया गया है। 2015 में दुनिया में मुसलमानों की आबादी 180 करोड़ थी। यह अनुमान है कि 2060 तक यह 300 करोड़ को पार कर जाएगी। प्यू रिसर्च सेंटर ने 2010 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया की मुस्लिम आबादी में से 34 फीसदी 15 साल से कम उम्र के हैं। वहीं, 60 फीसदी 15 से 59 साल के बीच हैं। महज 7 फीसदी मुस्लिम आबादी ही 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की है।

भारत में मुसलमानों की स्थिति क्या होगी: भारत में मुसलमानों की आबादी में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, 2060 तक भारत की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 19.4 प्रतिशत हो जाएगी, जबकि 2015 में यह 14.9 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगले 36 सालों में भारत में मुसलमानों की आबादी 33 करोड़ हो जाएगी।

हिंदुओं की आबादी सिर्फ 27 फीसदी बढ़ेगी: प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगले कुछ वर्षों में ईसाइयों की आबादी 34व बढ़ेगी, जबकि हिंदुओं की आबादी सिर्फ 27 प्रतिशत बढ़ेगी। यह दुनिया की आबादी बढ़ने की औसत दर से कम है। अभी ईसाई और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग दुनिया की आबादी का क्रमशः 34 प्रतिशत और 15 प्रतिशत हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया में धार्मिक जनसंख्या में बदलाव हो रहा है।

कितनी तेजी से बढ़ रही है मुस्लिम आबादी : प्यू रिसर्च सेंटर ने दुनिया के 201 देशों की आबादी का अध्ययन किया है। उसके अनुसार, पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। वहीं, ईसाइयों की आबादी तेजी से सिकुड़ रही है। महज 10 साल में ही ईसाई आबादी में काफी कमी आई है। 2010 में मुस्लिम आबादी दुनिया की आबादी का 23.9 फीसदी और ईसाई आबादी 30.6 फीसदी थी। वहीं, 2020 में मुस्लिम आबादी पूरी दुनिया की 25.6 फीसदी और ईसाइयों की आबादी 28.6 फीसदी हो गई। (यह लेखक के अपने विचार हैं)

कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 की घोषणा तीर्थयात्रा से कहीं अधिक ज्यों मायने रखती है?

विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त तक होगी। मंत्रालय ने कहा, इस साल, पांच बैच जिनमें से प्रत्येक में 50 यात्री होंगे और 10 बैच जिनमें से प्रत्येक में 50 यात्री होंगे, क्रमशः उत्तराखंड राज्य से लिपुलेख दर्रे को पार करते हुए और सिक्किम राज्य से नाथू ला दर्रे को पार करते हुए यात्रा करने वाले हैं. आवेदनों की स्वीकृति के लिए वेबसाइट खोल दी गई है. आवेदकों में से यात्रियों का चयन निष्पक्ष, कंप्यूटर द्वारा तैयार रैंडम और लिंग-संतुलित चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

(अरुणिम भैय्यन)

महामारी संबंधी व्यवधानों, कूटनीतिक चुनौतियों और विकास के भू-राजनीतिक गतिशीलता से भरे अंतराल के बाद, भारत सरकार द्वारा 2025 में कैलाश मानसरोवर यात्रा की घोषणा एक पवित्र तीर्थयात्रा मार्ग को फिर से खोलने से कहीं अधिक है।

यह सांस्कृतिक कूटनीति, सॉफ्ट पावर और आध्यात्मिक तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रति घरेलू पहुंच का एक जानबूझकर किया गया मिश्रण दर्शाता है. जैसे-जैसे तैयारियां शुरू होती हैं यह कदम आने वाले वर्ष के लिए भारत की व्यापक क्षेत्रीय रणनीतियों और आंतरिक प्राथमिकताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त तक होगी। मंत्रालय ने कहा, इस साल, पांच बैच जिनमें से प्रत्येक में 50 यात्री होंगे और 10 बैच जिनमें से प्रत्येक में 50 यात्री होंगे, क्रमशः उत्तराखंड राज्य से लिपुलेख दर्रे को पार करते हुए और सिक्किम राज्य से नाथू ला दर्रे को पार करते हुए यात्रा करने वाले हैं. आवेदनों की स्वीकृति के लिए वेबसाइट खोल दी गई है. आवेदकों में से यात्रियों का चयन निष्पक्ष, कंप्यूटर द्वारा तैयार रैंडम और लिंग-संतुलित चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

मंत्रालय ने आगे कहा कि आवेदकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र या फैक्स भेजने की आवश्यकता नहीं है. वेबसाइट पर फीडबैक विकल्पों का उपयोग जानकारी प्राप्त करने, टिप्पणियां दर्ज करने या सुधार के लिए सुझाव देने के लिए किया जा सकता है. शनिवार की यह घोषणा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल द्वारा इस महीने की शुरुआत में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दिए गए बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि तीर्थयात्रा इस वर्ष होगी।

2025 के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में भारत सरकार की घोषणा भारत-चीन संबंधों में सूक्ष्म पुनर्संतुलन का

संकेत देती है. क्षेत्रीय अस्थिरता और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अभी भी कुछ अनसुलझे तनावों के समय में आने वाला यह कदम बीजिंग के दृष्टिकोण और नई दिल्ली की रणनीतिक सोच की गहन जांच को आमंत्रित करता है।

पिछले महीने बीजिंग में आयोजित भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की 33वीं बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा था. भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पूर्वी एशिया) गौरांगलाल दास ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय मामलों के विभाग के महानिदेशक हांग लियान्ग ने किया।

बैठक के बाद जारी प्रेस वृत्तिप में विदेश मंत्रालय ने बताया कि चर्चा ‘सकारात्मक और रचनात्मक माहौल’ में हुई. इसमें एनएससी पर स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई. बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। दोनों पक्षों ने दिसंबर 2024 में बीजिंग में आयोजित 23वीं विशेष प्रतिनिधि बैठक के परिणामों को लागू करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया और राजनयिक और सैन्य संचार चैनलों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की. उन्होंने सीमा पार नदियों और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर सहयोग सहित सीमा पार आदान-प्रदान को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

कैलाश मानसरोवर यात्रा- तिब्बत में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की तीर्थयात्रा - हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और बौन अनुयायियों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है. 19500 फीट की ऊंचाई पर सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में से कुछ को पार करते हुए तीर्थयात्रा न केवल आस्था बल्कि शारीरिक सहनशक्ति का भी परीक्षण करती है. इसमें तीर्थयात्रियों को मौसम में बदलाव और ऊबड़-खाबड़ रास्तों को सहना पड़ता है। यात्रा का प्रबंधन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है.

यह वैध पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए खुला है और इसे भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) और सिक्किम पर्यटन विकास निगम (एसटीडीसी) सहित कई एजेंसियों के समन्वय से संचालित किया जाता है. दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट तीर्थयात्रियों की फिटनेस का आकलन करने के लिए कठोर चिकित्सा जांच करता है।

भारत सरकार इस बात पर जोर देती है कि तीर्थयात्री अपने जोखिम और खर्च कर यात्रा करते हैं. साथ ही जान-माल की हानि, चोट या संपत्ति के नुकसान के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है. उल्लेखनीय है कि तीर्थयात्रियों की मृत्यु की स्थिति में चीनी पक्ष में दाह संस्कार के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पार्थिव शरीर को वापस लाने की गारंटी नहीं होती है।

हालांकि यात्रा तक पहुंच अक्सर द्विपक्षीय संबंधों में उतार-चढ़ाव के कारण प्रभावित होती रही है. 2017 में चीन ने प्रतिकूल मौसम की स्थिति का हवाला देते हुए भारतीय तीर्थयात्रियों को नाथू ला दर्रे से प्रवेश करने से रोक दिया, जिससे लगभग 47 तीर्थयात्री प्रभावित हुए और राजनयिक आदान-प्रदान शुरू हो गया. 2023 में बीजिंग द्वारा उच्च शुल्क और अनिवार्य बायोमेट्रिक डेटा संग्रह सहित सख्त शर्तें लागू करने की रिपोर्ट सामने आई, जिससे तीर्थयात्रा और भी जटिल हो गई। चीन द्वारा उठाए गए ऐसे कदम अक्सर भू-राजनीतिक तनाव के दौर के समानांतर ही देखे गए हैं. यात्रा पर प्रतिबंधों को अक्सर सिर्फ रसद संबंधी बाधाओं के तौर पर नहीं बल्कि व्यापक भारत-चीन संबंधों की स्थिति को दर्शाते राजनीतिक संकेतों के तौर पर देखा जाता है।

सबसे हालिया व्यवधान 2020 के लद्दाख सीमा गतिरोध के दौरान आए थे, लेकिन अक्टूबर 2024 में कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक के बाद संबंधों में धीरे-धीरे सुधार हुआ.

निरिक्षण दिया गया। इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा सड़क सुरक्षा मिशन को बताया कि ‘‘राहवीर योजना’’ एक सैवैक्षिक कार्यक्रम अथवा निरीक्षण सहायता कार्यक्रम है। इसमें कोई भी आम व्यक्ति जो दुर्घटना के बाद घायल को सुरक्षित नर्सरी की अस्पताल तक पहुँचाता है, उसे 25 हजार रूपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना का यह भी उद्देश्य है कि ऐसे नागरिकों को किसी तरह की कानूनी कर्वाही या पूछताछ का सामना न करना पड़े।

निरिक्षण कार्यक्रम दौरान पुलिस अधीक्षक जांजीगीर विजय कुमार पाण्डेय अति. पुलिस अधीक्षक जांजीगीर उमेश कुमार कश्यप, अति. पुलिस अधीक्षक गायानात उदयन बेहरा, डीएसपी अजक जितेन्द्र खुंटे, उद्यन डी ओ पी चाम्पा युदुमणि सिदार्, डीएसपी (मुख्यालय) विजय यंकरा, एसडीओपी जांजीगीर प्रदीप कुमार सोरी, डीएसपी श्रीमती सत्यलका रामटेके, निरीक्षण महानिरीक्षक प्रदीप कुमार जोशी तथा रक्षित थेथाना/चैकी प्रभारीगण उपस्थित रहे।

